



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 16, 1990/आश्विन 24, 1912

No. 602] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 1990/ASVINA 24, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1990

का० प्रा. 799(अ):— केन्द्रीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रियक निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 4 और पूर्वोक्त क्लेज (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम और मेघालय राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन गठित और असम तथा मेघालय राज्यों में कार्यरत असम राज्य भेषजी परिषद्, जो एक नियमित निकाय है, के पुनर्गठन और पुनर्संगठन से संबंधित मेघालय सरकार द्वारा भेजी गई स्कीम को, कतिपय उपान्तरणों सहित, अनुमोदित करती है और इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम असम राज्य भेषजी परिषद् (पुनर्गठन और पुनर्संगठन) आदेश, 1960 है;

(2) यह अप्रैल 1, 1991 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :—(1) इन आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत दिन" से इस आदेश के प्रारम्भ की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) "विद्यमान परिषद्" से अधिनियम के अधीन गठित और असम राज्य में नियत दिन से ठीक पूर्व कार्यरत और सक्रिय-रत असम राज्य भेषजी परिषद्, जैसी कि वह 21 जनवरी, 1972 से ठीक पूर्व विद्यमान थी, अभिप्रेत है ;

(घ) "मेघालय परिषद्" से अधिनियम के अधीन मेघालय राज्य के लिए नियत दिन से गठित मेघालय राज्य भेषजी परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "असम परिषद्" से अधिनियम के अधीन असम राज्य के लिए नियत दिन से गठित असम राज्य भेषजी परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) विद्यमान परिषद् के संघ में "उत्तराधिकारी परिषद् से असम परिषद् या मंत्रालय परिषद् अभिप्रेत है।

(2) उन सभी शर्तों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस आदेश में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. विद्यमान परिषद् का विघटन और असम तथा मंत्रालय राज्यों के लिए पृथक् पृथक् भेजजी परिषदों का गठन नियत दिन से—

(क) विद्यमान परिषद् का विघटन हो जाएगा और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे:

परन्तु अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (छ) के अधीन असम राज्य का, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से ठीक पूर्व विद्यमान था, केन्द्रीय परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यमान परिषद् द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति अपनी पदावधि के अवसान तक या असम परिषद् द्वारा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति का निर्वाचन किए जाने तक, उनमें से ओ भी पश्चात्तर्वर्ती हों, केन्द्रीय परिषद् का सदस्य बना रहेगा।

(ख) असम सरकार, इस आदेश द्वारा उपात्तरित रूप में अधिनियम की धारा 19क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में असम राज्य के लिए एक भेजजी परिषद् का गठन करेगी;

(ग) मंत्रालय सरकार, इस आदेश द्वारा उपात्तरित रूप में अधिनियम की धारा 19क की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में मंत्रालय राज्य के लिए एक भेजजी परिषद् का गठन करेगी;

(घ) खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन गठित भेजजी परिषद् के सदस्य, अधिनियम की धारा 25 में किसी बात के होते हुई भी, नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि तक या उस अवधि तक या उस अवधि तक, जब तक अधिनियम की धारा 19 के अधीन उक्त परिषद् का सम्पन्न रूप से गठन नहीं हो जाता, इनमें से ओ भी पूर्वतः हो, पद धारण करेंगे; और

(ङ) खण्ड (ख) और (ग) के अधीन गठित प्रत्येक भेजजी परिषद् के सभापति और उप सभापति को, अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस राज्य की सरकार जिसके लिए उक्त परिषद् का गठन किया गया है, भेजजी परिषद् के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट करेगी।

4. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति— (1) विद्यमान परिषद् का रजिस्ट्रार जो नियत दिन से ठीक पूर्व पद धारण कर रहा है उसी दिन से ही असम परिषद् का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रार को लागू होने वाले सेवा के नियमों और शर्तों, जब तक वे अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित न कर दी जाए, वही होंगी जो उस दिन से ठीक पूर्व उसे लागू थी।

(2) जब तक मंत्रालय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा सम्पन्न रूप से नियुक्त नहीं कर दिया जाता है तब तक के लिए मंत्रालय सरकार ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे उक्त परिषद् के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी।

5. रजिस्ट्रार के संबंध में उपबंध— अधिनियम के अधीन सम्पन्न रखा गया और नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त रजिस्ट्रार असम और मंत्रालय दोनों राज्यों के लिए रखा गया रजिस्ट्रार समझा जाएगा और तदनुसार ऐसे रजिस्ट्रार पर अंकित भेजजों के नाम किसी अतिरिक्त फीस या प्रभार के बिना अधिनियम की धारा 36 के उपबंधों के अधीन रहते हुए दिन से छह मास की अवधि तक उसमें बने रहेंगे और

तत्पश्चात् उसका नाम उक्त दोनों राज्यों में से किसी ऐसे एक राज्य में बना रहूँगे जिस राज्य में वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस अवधि के दौरान संबंधित उत्तराधिकारी परिषद् के रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में अपना रजिस्ट्रार बनाना रखने की इच्छा व्यक्त करता है।

6. बकाया फीसों और अन्य शोध्य रकमों की बसुली— अधिनियम के अधीन नियत दिन तक विद्यमान परिषद् को सदैव सभी फीसों और अन्य शोध्य रकमों—

(क) यदि शोध्य रकमों किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सदैव हैं जो सामान्यतः किसी उत्तराधिकारी परिषद् के क्षेत्र में निवास कर रहा है, उक्त परिषद् द्वारा बसुली की जाएगी; और

(ख) किसी अन्य मामले में असम परिषद् द्वारा बसुली की जाएगी।

7. विद्यमान परिषद् के नकद अतिशेष का विभाजन— नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान परिषद् द्वारा धारित नकद अतिशेष, उक्त परिषद् के उस दिन तक के सभी वास्तविक की कटौती करने के पश्चात् उत्तराधिकारी परिषदों के बीच, प्रत्येक उत्तराधिकारी परिषद् के क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे रजिस्ट्रीकृत भेजजों की संख्या के अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे।

8. अवशिष्ट उपबंध— नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान परिषद् को कोई अन्य आस्तियाँ या दायित्व, जो अभिव्यक्त रूप से इसमें इसके पूर्व उपबंधित नहीं हैं, पैरा 7 में उपदिष्ट रीति में प्रभाजित किए जाएंगे।

9. विधि कार्यवाहियाँ जहाँ नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान परिषद् किसी न्यायालय में किसी रजिस्ट्रीकृत भेजज या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्था किन्हीं विधिक कार्यवाहियों की पक्षकार है वहाँ वह उत्तराधिकारी परिषद्, जिसके क्षेत्र के भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकृत भेजज या अन्य व्यक्ति सामान्यतः निवास कर रहा है, उन कार्यवाहियों में एक पक्षकार के रूप में विद्यमान परिषद् के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी और कार्यवाहियाँ तदनुसार चालू रहेंगी।

10. संविदाएँ— जहाँ नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान परिषद् ने कोई ऐसी संविदा की है, जो उस दिन को अस्तित्व में है वहाँ—

(क) यदि संविदा के प्रयोजन नियत दिन किसी उत्तराधिकारी परिषद् के क्षेत्र से अनन्यतः संबंधित है तो ऐसी संविदा उस परिषद् द्वारा की गई समझी जाएगी।

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसी संविदा असम परिषद् द्वारा की गई समझी जाएगी और वे सभी अधिकार और दायित्व जो ऐसी किसी संविदा के अधीन उद्भूत हुए हैं या उद्भूत हो सकते हैं उस सीमा तक जहाँ तक वे विद्यमान परिषद् के अधिकार और दायित्व हों, समुचित उत्तराधिकारी परिषद् के अधिकार और दायित्व होंगे।

11. विद्यमान परिषद् के समस्त लम्बित कतिपय कार्यवाहियों का अन्तरण—

किसी रजिस्ट्रीकृत भेजज या अन्य व्यक्ति से संबंधित कोई कार्यवाहियाँ जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान परिषद् के समस्त लम्बित हैं, उसी दिन से उस उत्तराधिकारी परिषद् को, जिसके क्षेत्र के भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकृत भेजज या अन्य व्यक्ति सामान्यतः निवास कर रहा है, विधि के अनुसार निपटाए जाने के लिए अंतरित हो जाएगी।

12. व्याप्ति:—विद्यमान परिषद् द्वारा या उसकी बाबत विरचित सभी नियम और विनियम, जब तक कि संसद उत्तराधिकारी परिषद् के संबंध में अधिनियम के अधीन अन्य उपबंध नहीं किए जाते, उस परिषद् द्वारा या उसके संबंध में विरचित नियम और विनियम समझे जाएंगे और यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उन पर लागू होते रहेंगे।

13. अधिनियम के अपवाद और उन्नांतरण— अधिनियम नियत दिन से ही, जब तक उसे सक्षम विद्यमान मण्डल द्वारा परिवर्तित, निरस्तित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए असम और मेघालय राज्यों में प्रभावी होगा।

अनुसूची

(पैरा 13 देखिए)

भेषजी अधिनियम, 1948

(1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 8)

1. धारा 2 के खण्ड (घ) में "धारा 19" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 18क" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे:—

1. धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"19क. राज्य परिषदों की बाबत अस्थायी उपबंध:—

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(1) धारा 19 के अधीन गठित और अन्तर्राज्यिक निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 4 के अधीन जारी किए गए असम राज्य भेषजी परिषद् (पुनर्संगठन और पुनर्गठन) आदेश, 1990 में यथा परिभाषित नियत दिन से ठीक पूर्व असम और मेघालय राज्यों में कार्यरत और संक्रिया-यारत असम राज्य भेषजी परिषद् उसी दिन से ही विघटित हो जाएगी और धारा 25 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसके सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट दिन से असम सरकार असम राज्य के लिए धारा 19 में विनिर्दिष्ट रीति में एक परिषद् का गठन करेगी जो असम राज्य भेषजी परिषद् के नाम से ज्ञात होगी:

परन्तु धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भेषजों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले छह सदस्य और उस धारा के खण्ड (ग) के अधीन राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला सदस्य भी असम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) खण्ड (1) में निर्दिष्ट दिन से मेघालय सरकार, मेघालय राज्य के लिए धारा 19 में विनिर्दिष्ट रीति में एक परिषद् का गठन करेगी जो मेघालय राज्य भेषजी परिषद् के नाम से ज्ञात होगी:

परन्तु धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भेषजों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले छह सदस्य और उस धारा के खण्ड (ग) के अधीन राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला सदस्य भी मेघालय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन गठित असम राज्य भेषजी परिषद् और मेघालय राज्य भेषजी परिषद् के सदस्य धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (1) में निर्दिष्ट दिन से पांच वर्ष की अवधि तक या उस अवधि तक, जब तक

धारा 19 के अधीन परिषद् का सभ्यक रूप से गठन नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।

(5) खण्ड (2) और (3) के अधीन गठित प्रत्येक परिषद् के सभापति और उपसभापति को धारा 23 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस राज्य की सरकार द्वारा जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया है, राज्य परिषद् के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"29. रजिस्ट्रारों की बाबत अस्थायी उपबंध:— ऐसे सभी भेषज जिनके नाम अंतर्राज्यिक निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 4 के अधीन जारी किए गए असम राज्य भेषजी परिषद् (पुनर्संगठन और पुनर्गठन) आदेश, 1990 में यथा परिभाषित नियत दिन से ठीक पूर्व इस अधिनियम के अधीन रखे गए रजिस्टर पर थे उसी दिन से ही धारा 36 के उपबंधों के अधीन रहते हुए असम और मेघालय राज्यों के रजिस्ट्रारों में नियत दिन से छः मास की अवधि तक किसी फीस या अतिरिक्त प्रभार के बिना उसमें बने रहेंगे और तत्पश्चात् उसका नाम उक्त दोनों राज्यों में से किसी ऐसे एक राज्य में बना रह सकेगा जिस राज्य में वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस अवधि के दौरान संबंधित उत्तराधिकारी परिषद् के रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में अपना रजिस्ट्रारकण बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करता है।

[सं० एस 12014/12/74—एस० आर]

जगदीश चन्द्र डंगवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 15th October, 1990

S.O. 799(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957) and section 56 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government, after consulting the Governments of the States of Assam and Meghalaya hereby approves, with certain modifications the scheme forwarded by the Government of Meghalaya relating to the reconstitution and reorganisation of the Assam State Pharmacy Council, being a body corporate constituted under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) and functioning in the States of Assam and Meghalaya and, for the purpose of giving effect to the scheme so approved, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Assam State Pharmacy Council (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1990.

(2) It shall come into force on the First April, 1991.

2. Definitions.—(1) In this order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);

(b) "appointed day" means the date of commencement of this Order;

- (c) "existing Council" means the Assam State Pharmacy Council, constituted under the Act and functioning and operating immediately before the appointed day, in the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972;
- (d) "Meghalaya Council" means Meghalaya State Pharmacy Council constituted under the Act as from the appointed day, for the State of Meghalaya;
- (e) "Assam Council" means the Assam State Pharmacy Council constituted under the Act as from the appointed day, for the State of Assam;
- (f) "successor Council" in relation to the existing Council means the Assam Council or the Meghalaya Council.
- (2) All other words and expressions used herein but not defined in this Order shall have the meanings assigned to them in the Act.
- (3) Dissolution of the existing Council and constitution of separate Pharmacy Councils for the States of Assam and Meghalaya.—As from the appointed day,—
- (a) the existing Council shall stand dissolved and the members thereof shall vacate their offices;
- Provided that any person elected by the existing Council under clause (g) of section 3 of the Act, as a member representing the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, on the Central Council, shall continue to hold the membership of the Central Council, until the expiry of the term of his office or until the election of another person in his place by the Assam Council, whichever is later;
- (b) the Government of Assam shall constitute a Pharmacy Council for the State of Assam in the manner specified in sub-section (2) of section 19A of the Act as modified by this Order;
- (c) the Government of Meghalaya shall constitute a Pharmacy Council for the State of Meghalaya in the manner specified in sub-section (3) of section 19A of the Act, as modified by this Order;
- (d) the members of the Pharmacy Council constituted under clause (b) or clause (c) shall, notwithstanding anything contained in section 25 of the Act, hold office for a period of five years from the appointed day or until such time as the said Council is duly constituted under section 19 of the Act, whichever is earlier; and
- (e) the President and Vice-President of each of the Pharmacy Councils constituted under clauses (b) and (c) shall, notwithstanding

anything contained in sub-section (1) of section 23 of the Act, be nominated from amongst the members of the Pharmacy Council by the Government of the State for which the said Council has been constituted.

4. Appointment of Registrars.—(1) The Registrar of the existing Council, holding office immediately before the appointed day, shall as from that day, be deemed to have been appointed as the Registrar of the Assam Council and the terms and conditions of service applicable to the Registrar shall be the same as were applicable to him immediately before that day, until they are varied by a competent authority under the Act.

(2) Until a Registrar is duly appointed by the Meghalaya Council under section 26 of the Act, the Government of Meghalaya shall appoint a Registrar for the said Council on such terms and conditions as it deems fit.

5. Provision regarding register.—The register duly maintained under the Act in force immediately before the appointed day, shall be deemed to be the register for each of the States of Assam and Meghalaya and accordingly the names of pharmacists on such register shall, without further fee or charge, be continued thereon subject to the provisions of section 36 of the Act for a period of six months from the appointed day and thereafter on the register of any of the said States in which the registered person concerned expresses his desire to continue his registration by a letter addressed to the Registrar of the successor Council concerned within that period.

6. Recovery of outstanding fees and other dues.—All fees and other dues payable to the existing Council under the Act upto the appointed day shall,—

- (a) if the dues are payable by a person ordinarily residing in the area of any successor Council, be recovered by that Council; and
- (b) in any other case, be recovered by the Assam Council.

7. Division of Cash balance of the existing Council.—The cash balance held by the existing Council immediately before the appointed day, shall, after deduction of all the liabilities of that Council upto that day, be apportioned among the successor Councils in proportion to the number of registered pharmacists ordinarily residing in the area of each successor Council.

8. Residuary provision.—Any other assets or liabilities of the existing Council immediately before the appointed day, not expressly herein-before provided for, shall be apportioned in the manner indicated in paragraph 7.

9. Legal proceedings.—Where immediately before the appointed day, the existing Council is a party to any legal proceedings instituted in any court, by or against any registered pharmacists or other person,

the successor Council within whose area such registered pharmacist or other person is ordinarily residing shall be deemed to be substituted for the existing Council as a party to those proceedings and the proceeding may continue accordingly.

10. Contracts.—Where immediately before the appointed day, the existing Council has made any contract which on the day is subsisting, such contract shall be deemed to have been made—

- (a) if the purposes of the contract are, as from the appointed day, exclusively relatable to the area of any successor Council, by that Council;
- (b) in any other case, by the Assam Council and all rights or liabilities which have accrued or may accrue under any such contract shall, to the extent to which they would have been the rights or liabilities of the existing Council, be the rights or liabilities of the appropriate successor Council.

11. Transfer of certain proceedings pending before the existing Council.—Any proceedings relating to any registered pharmacist or other person which are pending immediately before the appointed day before the existing Council, shall on that day stand transferred to that successor Council within whose area such registered pharmacist or other person is ordinarily residing, for disposal according to law.

12. Saving.—All rules and regulations framed in respect of or by the existing Council, shall, until other provision is made under the Act in respect of the relevant successor Council, be deemed to be the rules and regulations framed in respect of or by that Council and shall continue to apply to them *mutatis mutandis*.

13. Exceptions and modifications in the Act.—As from the appointed day, the Act shall, until altered, repealed or amended by the competent legislature, have effect in the States of Assam and Meghalaya subject to the exceptions and modifications specified in the Schedule annexed hereto.

THE SCHEDULE

(See Paragraph 13)

THE PHARMACY ACT, 1948

(Central Act 8 of 1948)

1. In clause (j) of section 2, after the word and figure "section 19", the words and figure "or section 19A" shall be inserted.

2777 GI/90-2

2. After section 19, the following section shall be inserted, namely :—

"19A. Temporary provisions in respect of State Councils.—Notwithstanding anything contained in this Act,—

- (1) the Assam State Pharmacy Council constituted under section 19 and functioning and operating in the States of Assam and Meghalaya, immediately before the appointed day as defined in the Assam State Pharmacy Council (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1990, issued under section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957), shall, as from the day, stand dissolved and the members thereof shall, notwithstanding anything contained in section 25, vacate their office.
- (2) as from the day referred to in clause (1), the Government of Assam shall constitute a Council for the State of Assam, in the manner specified in section 19, to be known as Assam State Pharmacy Council:

Provided that, the six members to be elected by registered pharmacist under clause (a) of section 19 and the member to be elected by the Medical Council of the State under clause (c) of that section, shall also be nominated by the Government of Assam.

- (3) as from the day referred to in clause (1), the Government of Meghalaya shall constitute a Council for the State of Meghalaya in the manner specified in section 19, to be known as the Meghalaya State Pharmacy Council.

Provided that, the six members to be elected by registered pharmacist under clause (a) of section 19 and the member to be elected by the Medical Council of the State under clause (c) of that section, shall also be nominated by the Government of Meghalaya.

- (4) the members of the Assam State Pharmacy Council and the Meghalaya State Pharmacy Council constituted under this section shall, notwithstanding anything contained in section 25, hold office for a period of five years from the day referred

to in clause (1) or until such time as a Council is duly constituted under section 19, whichever is earlier.

- (5) the President and Vice-President of each of the Councils constituted under clauses (2) and (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 23, be nominated from amongst the members of the State Council by the Government of the State for which the Council has been constituted."

3. After section 29, the following section shall be inserted, namely :—

"29A. Temporary provision in respect of registers.—All pharmacists who immediately before the appointed day as defined in the Assam State Pharmacy Council (Recons-

titution and Reorganisation) Order, 1990 issued under Section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957), were on the registered maintained under this Act, shall, on and from that day, without further fee or charge, continue, subject to the provisions of section 36, to be on the register of the States of Assam and Meghalaya for a period of six months from the appointed day and thereafter on the register of any of the said States in which the registered person concerned expresses his desire to continue his registration by a letter addressed to the Registrar of the successor Council concerned within that period."

[No. S-12014/12174-SR]

J. C. DANGWAL, Jt. Secy.